International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp.57-60

सतत् विकास एवं गरीबी उन्मूलन के सन्दर्भ में हरित अर्थव्यवस्था

चैनाराम (मुंदलिया)*
डॉ. ओमप्रकाश शर्मा**

सार

वैश्विक विकास की वर्तमान अवधारणा हमें एक ऐसे रास्ते की ओर ले जा रही है जहां से वापस लौटना हमारे लिए मुश्किल ही नही ना मुमकिन होगा। दुनिया ने विकास की जिस रफ्तार को अपनाया है उससे एक ओर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वही दूसरी ओर उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे है। परन्तु 21 वीं सदी के शुरूआती वर्षों में विश्व के सामने इन दुष्परिणामों से बचने एवं टिकाऊ विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा उभर कर सामने आयी है। आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हरित अर्थव्यवस्था की धारणा पल्लवित हो रही है। जिसका उदेश्य पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिक संकटों को कम करना तथा पर्यावरण के अनुकूल विकास करना है।

2011 में यूएनईपी के प्रतिवेदन में बताया गया है कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था को न केवल कुशल अपितु निष्पक्ष भी होना चाहिए अर्थात उसे निम्न कार्बन उत्सर्जन, संसाधन प्रबंध और सामाजिक रूप से समावेशी होना चाहिए। हरित अर्थव्यवस्था ऐसी ही निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का परिचायक है। यद्यपि इसकी अपनी चिन्ताएं भी है परन्तु वैश्वीकरण के दौर में सतत विकास एवं वैश्विक निर्धनता जैसी चुनौतियों के निदान में यह एक प्रभावी कदम हो सकती है। इस पर्चे का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण एवं विकास के वर्तमान मॉडल से वैश्विक स्तर पर उभर रहे पर्यावरणीय संकट एवं सामाजिक विषमता जैसी समस्याओं तथा इन समस्याओं के निदान हेतु सतत विकास एवं उसके अगले कदम ग्रीन इकॉनामी के दृष्टिकोण से विचार करना है। ग्रीन इकॉनामी के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ विकास एवं समता पर आधारित सामाजिक विकास पर चर्चा केन्द्रित रहेगी।

***शब्दावलीः** सतत् विकास, वैश्विक निर्धनता, ग्रीन इकॉनामी, कार्बन उत्सर्जन, समावेशी विकास।*

परिचय

21 वी सदी के शुरूआती वर्षों में हरित अर्थव्यवस्था की धारणा एक लोकप्रिय वैश्विक अवधारणा बन रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण भी है। ऐसा अनुमान है कि फिलहाल विश्व जिन संकटों यथा : जलवायु, खा़द्य एवं आर्थिक का सामना कर रहा है उन सबके समाधान की क्षमता हरित अर्थव्यवस्था के पास है। यह आर्थिक विकास के साथ पृथ्वी को पारिस्थितिकी प्रणाली की सुंरक्षा की गारंटी भी प्रदान करता है। वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी आलोच्य अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता एवं वांछनीयता के लिए अवसर प्रदान किया। इसी परिप्रेक्ष्य में यूएनईपी के तत्वावधान में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में 1992 के सतत विकास की अवधारणा की थीम वाले सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद पुनः जून, 2012 में रियो +20 सम्मेलन 'सतत विकास एवं गरीबी उन्मुलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था के नाम से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था।

आज वैश्विक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चाएं, बैठक, सम्मेलन आयोजित हो रहे है। तात्पर्य यह है कि वैश्विक स्तर पर सतत् विकास जिस कदर विगत दशक में चर्चा का मुख्य वैश्विक विषय रहा है ठीक उसी प्रकार आने वाले दशकों में हरित अर्थव्यवस्था कुछ ऐसा ही विषय बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, नागौर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक, जयपुर, राजस्थान।

कार्यक्रम के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था एक ओर जहां सवंद्धित मानव भलाई और सामाजिक साम्यता को बढ़ावा देता है तो दूसरी ओर पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिकीय संकट को भी कम करता है। हरित अर्थव्यवस्था की सरलतम अभिव्यक्ति है अल्प कार्बन, संसाधन कुशल व सामाजिक समावेशन वाली अर्थव्यवस्था।

हरित अर्थव्यवस्था से आशय

व्यावहारिक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आय व रोजगार में वृद्धि उस सार्वजनिक व निजी निवेश द्वारा संचालित होती है जो कि कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषण को कम करता है, ऊर्जा व संसाधन की दक्षता बढ़ाता है तथ जैव विविधता व पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं के क्षय को रोकता है। इन निवेशों को लक्षित सार्वजनिक व्यय, नीतिगत सुधारों और विनियमन परिवर्तन के द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित करने की आवश्यकता है। इस विकास के रास्ते को बनाए रखना और सुदृढ़ करना आवश्यक है और जहां आवश्यक हो, दयनीय आर्थिक संपदाओं व सार्वजनिक लाभों के स्रोंतो के रूप में प्राकृतिक पूंजी के पुनर्निर्माण भी किया जाना चाहिए। विशेष रूप से गरीब लोग जिनकी आजीविका और सुरक्षा मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर है।

हरित अर्थव्यवस्था मापन के कारक

हरित अर्थव्यवस्था के मापन हेतु विभिन्न संगठन विभिन्न तरीके अपनाते रहे है। इसके लिए कई संकेतकों का प्रयोग होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसके मापन हेतु ओईसीडी तथा विश्व बैंक के साथ कई कारकों पर चर्चा कर रहा है। मुख्यतः जो कारक उभर कर आए है उनमें प्रमुख निम्नांकित है–

- आर्थिक संकेतक : सतत् मानकों को पुरा करने वाले क्षेत्रकों में निवेश का हिस्सा या उत्पादन का हिस्सा या रोजगार जैसे ग्रीन जीडीपी
- पर्यावरणीय संकेतक : या तो क्षेत्रक या आर्थिक स्तर पर संसाधन प्रयोग क्षमता या प्रदूषण गहनता। जैसे ऊर्जा उपयोग/जीडीपी या जल उपभोग/जीडीपी
- प्रगति या अच्छे रहन – सहन का समन्वित संकेतक।

वैसे हरित अर्थव्यवस्था के घटकों पर यूएनईपी के अलावा कई संगठनों ने भी अपना विश्लेषण दिया है। कार्ल बुकार्ट ने हरति अर्थव्यवस्था के छह घटक यथा : अक्षय ऊर्जा, ग्रीन बिल्डिंग, स्वच्छ परिवहन,जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा भूप्रबंधन बताये है।

ग्लोबल सिटीजंस सेंटर ने हरित अर्थव्यवस्था के तीन स्तम्भ माने है जिसे वह **'तिहरी आधार रेखा'** कहता है। ये तीन स्तंभ है – टिकाऊ विकास, सामाजिक न्याय तथा स्थानीयता। जिसे निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है।

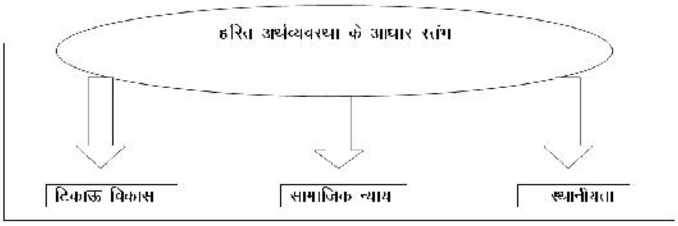

ग्लोबल ग्रीन इकानॉमी जो कि ड्युल सिटीजन इंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इसके लिए यह चार संकेतकों का सहारा लेता है –

- राष्ट्रीय नेतृत्व किस हद तक स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हरित मुद्दों पर अपना नेत्त्व प्रदान करता है।
- घरेलू बाजार में अक्षय ऊर्जा स्रोतो के उपयोग को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने वाली नीतिगत ढ़ाचा व घरेलू नीतियों की सफलता।
- प्रत्येक देश में स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश माहौल
- ग्रीन पर्यटन एवं सरकार के माध्यम से सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिब़द्धता।

सतत् विकास में हरित अर्थव्यवस्था की भूमिका

सतत् विकास वह है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ीयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ समझौता नहीं करे। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता वर्ष 1980 में **अवर कॉमन फ्यूचर'** नाम से ब्रंटलैंड' प्रतिवेदन से हासिल हुई और फिर 1992 में रियो डी जेनेरिया में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य निर्देशक सिद्धान्त के रूप में इसे पहचान मिली। सतत् विकास हासिल करने के लिए अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से मजबूत तीन स्तंभों में उन्नति व मजबूती की दरकार होती है। ये तीन स्तंभ हैं – पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न कचरों के निष्क्रिय ग्राही के बजाय, हरित अर्थव्यवस्था में पर्यावरण को आर्थिक उत्पादन, मूल्य स्थिरता व दीर्घावधिक समृद्धि के लिए एक आर्थिक कारक माना जाता है जो कि वास्तव में विकास और नवाचार के लिए एक प्रेरणास्रोत होता है। हरित अर्थव्यवस्था में पर्यावरण आर्थिक विकास व मानव भलाई का संबल होता है। इसके अतिरिक्त गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं तथा पर्यावरण के अपक्षय से रक्षा रूपी उनकी ढ़ाल सबसे कमजोर होता है, ऐसे में हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आंदोलन समान विकास को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार हरित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुकता सतत् विकास का एक मार्ग है। साथ ही इसे गंतव्य के बजाय एक यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। वैसे विकसित व विकासशील देशों के बीच हरित अर्थव्यवस्था की प्रकृति में भौगोलिक सीमा, प्राकृतिक संसाधन आधार, मानव और सामाजिक पूजी और आर्थिक विकास के चरण के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकता है, पर इसके मुख्य सिद्धान्तों यथा : सवंर्द्धित मानव भलाई, सामाजिक समानता, पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिक अपक्षय को कम करना इत्यादि में कोई भिन्नता नहीं है।

हरित अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन

आज आर्थिक संपदा जो कि सकल घरेलू उत्वाद के रूप में परिभाषित की जाती है, वह साधारणतया स्वच्छ ताजा जल, वन व हवा जैसे जीवन के लिए अनिवार्य हमारे साझा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं प्रदूषण से सृजित किए जाते है। इस तरह के आर्थिक विकास ने उच्च आर्थिक व सामाजिक लागत को जन्म दिया है, खासकर उन गरीबों के लिए जो अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः इन संसाधनों पर निर्भर रहे है। मौजूदा आर्थिक गतिविधियों से बड़े पैमाने पर जैव विविधता व पारिस्थितिकी प्रणाली का अपक्षय हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषि, पशुपालन, मत्स्यन व वनीकरण जैसे क्षेत्रक विशेष रूप से प्रभावित हुये है जिन पर विश्व की अधिकांश गरीब आबादी की आजीविका निर्भर है। वहीं दूसरी ओर हरित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुखता, गरीबी उन्मुलन एवं समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु बुनियादी सेवाओं तथा आधारित संरचना तक पहुचने का लक्ष्य लेकर चलती है। इसमें शामिल है – विश्व की उस आबादी तक बिजली एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना जो अभी तक इन सेवाओं से वंचित है। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय जोखिम को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को भी समाप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। एक अनूमान के मुताबिक फिलहाल दुनिया भर की सरकारें जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 700 अरब डॉलर वार्षिक व्यय करती है। यह रकम दुनिया भर में विकास सहायता पर होने वाले व्यय का पांच गुना है। इस सब्सिडी का अधिकांश भाग विकासशील देशों की सरकारों द्वारा गरीबों को वस्तुओं के मूल्यों में अकस्मात बढ़ोतरी से ढाल के रूप में आंवटित किया जाता है। पर कई अध्ययनों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि जीवाश्म ईधन सब्सिडी का वास्तविक लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है और उच्च आय वाले लोग इसका फायदा उठा ले जाते है। पर्यावरणीय जोखिम सब्सिडियों को समाप्त कर जरूरतमंदों को नकद हस्तांतरण जैसा तरीका अपनाने से राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इससे पर्यावरणीय निष्पादन में भी सुधार होगा।

सुझाव एवं निष्कर्ष

हरित अर्थव्यवस्था भले ही रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा सतत् विकास इत्यादि को बढावा देने का लक्ष्य लेकर चल रही हो तथा विश्व के नेता इसके प्रति आशान्वित भी है पर इसकी चिन्ताएं भी कम नहीं है और यह चिन्ता मुख्यतः विकासशील देशों की है। विकासशील देशों का मानना है कि हरित अर्थव्यवस्था उनके आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है। उनके मुताबिक हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा के दुरूपयोग से धनी और गरीब के बीच असमानता और बढ़ेगी ही, जो गरीबों का विकास अवरूद्ध कर सकती है। विकासशील देशों की मुख्य चिन्ता संरक्षणवाद तथा तकनीक के लिए विकसित देशों द्वारा अपने उद्योगो को दिया जाने वाला अनुदान है जिससे वे उद्योग अपने आप को पर्यावरण संगत बना सके। विकासशील देशो के सामने चुनौती विकास को बढावा देने के साथ साथ इसको बनाएं रखने की है। जबकि विकासति देश आर्थिक विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए है उनकों केवल विकास के स्तर को बनाए रखना है न कि विकास को बढाना है। ऐसी प्रतिस्पर्धा में नुकसान विकासशील देशो का ही होगा। परन्तु उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देशों को सहोगाात्मक कदम उठाना पड़ेगा तभी न्याय संगत व समता पर आधारित पर्यावरण अनुकूल वैश्विक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- गुर्जर एवं जाट : मानव व आर्थिक भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2006
- गौतम, अलका : विश्व का भूगोल, शारदा पुस्तक सदन, नई दिल्ली 2010
- चुतुर्वेदी, उमेश : हरित जीडीपी– संपोषणीय विकास का मार्ग, योजना दिसम्बर 2015
- Green Economy Roadmap". Archived from the original on 5 May 2016. Retrieved 11 May 2016.
- Leong, G.C. & Morgan, G.C ; Human & Economic Geography, Oxford University Press, Londan, 1982
- Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds Communicating Sustainability for the Green Economy. New York:. 2014
- Spash, C.L. 2008. How much is that ecosystem in the window? The one with the bio-diverse trail. Environmental Values, vol. 17, no. 2, 259-284
- United Nations Environment Programme (UNEP)". Archived from the original on 27 March 2016. Retrieved 11 May 2016.
- World Bank to lead economic push on nature protection". BBC News. Retrieved 11 May 2016.
- http://www.fcm.ca/Documents/reports/Ecological_Footprints_of_Canadian_Municipalities_and_Regions_EN.pdf (Reinhardt, 1999; King and Lenox, 2002; Wagner, 203; Wagner, et al., 2005).
- www.unep.org/greeneconomy Jump up to:[a b] UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication

❖◆❖